

2 जून को कुशीनगर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, डीएम-एसपी ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां वे 376 करोड़ रुपये की 271 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

(जीएनएस)। कुशीनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार को आगमन की तैयारियां जोर पर हैं। कार्यक्रम को लेकर भव्य बनाने के लिए अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मुख्यमंत्री यहां सुबह नौ बजे तमकुहीराज स्थित एनएचआई के पार्किंग ग्राउंड में 376 करोड़ की लागत से 271 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

इस दौरान वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रविवार को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे डीएम महेंद्र सिंह तंवर, एसपी केशव कुमार, सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम वैभव मिश्र, एसपी सिद्धार्थ वर्मा, एसडीएम



तमकुहीराज में एनएचआई के पार्किंग ग्राउंड में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर स्थल का जायजा लेते (दाएं से दूसरी) सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव, एसपी केशव कुमार, डीएम महेंद्र सिंह तंवर, विधायक डॉ. असीम राय आकांक्षा मिश्रा, सीओ जयंत यादव ने तैयारियों का जायजा लिए।

कार्यक्रम स्थल पर 5000 लोगों को बैठने की व्यवस्था

इस दौरान डीएम ने कार्यक्रम स्थल और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे हेलीपैड का निरीक्षण किया और गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था, पीने के

पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, मंच पर बैठने की व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने मातहतों को जरूरी निर्देश दिए। कहा कि एनएच के सर्विस रोड कार्यक्रम होने तक वैरिफिकेटिंग कर

दिया जाए। विधायक सर्विसलेन पर ही अपने वाहनों से उतरकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान विधायक डॉ. असीम कुमार राय ने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों से चर्चा की।

विधायक ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर 5000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर क्रम स्थल को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए 250 से अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने कहा कि सभी विभागों की अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की सफाई के लिए नगर पंचायत और ब्लॉक के सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। कहा कि कार्यक्रम स्थल के बगल में ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरगा।

राजीव कृष्ण ने स्थायी डीजीपी बनने के बाद की सीएम योगी से मुलाकात, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी का परिवार रसूखदार

यूपी का स्थायी डीजीपी बनने के बाद सीनियर आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। (जीएनएस)।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में करीब चार साल के बाद स्थायी डीजीपी की नियुक्ति हुई है। राज्य सरकार की ओर से पिछले साल 31 मई को राजीव कृष्ण कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए थे। कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के रिटायर होने के बाद उन्होंने बतौर कार्यवाहक डीजीपी कार्यभार संभाला। अब 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया स्थायी डीजीपी नियुक्त कर दिया है। उनके नाम पर अंतिम मुहर लगने के साथ ही यूपी पुलिस की नियमित नेतृत्व मिला है। यूपीएससी की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राजीव कृष्ण का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होगा।

सीएम से की मुलाकात यूपी के नवनिर्वाचित स्थायी डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। स्थायी डीजीपी के रूप



में तैनाती के बाद सीएम योगी से मुलाकात हुई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम योगी ने भी उन्हें स्थायी डीजीपी बनने की बधाई दी। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की ओर से राजीव

कृष्ण को स्थायी डीजीपी बनाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया। लखनऊ में दो बार संभाली

कमान

राजीव कृष्ण 1991 बैच के

का मौका मिला। मायावती सरकार के काल में राजीव कृष्ण लखनऊ के डीआईजी भी बनाए गए थे।

राजीव कृष्ण ने यूपी एटीएस के डीआईजी के रूप में भी अहम भूमिका निभाई। एटीएस को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। राजीव कृष्ण मेरठ रेंज के आईजी, लखनऊ और आगरा जौन के एडीजी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी।

परिवार भी है रसूखदार

राजीव कृष्ण का परिवार रसूखदार रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके परिवार की अलग पहचान है। उनकी पत्नी मीनाक्षी सिंह आईआरएस अधिकारी हैं। वे अभी सीबीडीटी में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं, लखनऊ के सरोजनीनगर विधायक राजेश्वर सिंह उनके साले हैं। साथ ही, गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह उनकी रिश्तेदार हैं।

ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर राज्यों में गणना चरण शुरू

(जीएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 मई, 2026 को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का आदेश दिया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु पात्रता तिथि पर अठारह वर्ष से कम न हो

और जो किसी अन्य कानून के तहत अपात्र न हो, मतदाता सूची में पंजीकरण करने का हकदार होगा।

चुनाव आयोग के दिनांक 14.05.2026 के आदेश के अनुसार, ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर राज्यों में 30.05.2026 से गणना चरण प्रारंभ हो गया है। वे सभी पात्र मतदाता जिनके गणना प्रपत्र निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को 28.06.2026 या उससे पहले प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

जो मतदाता 28.06.2026 तक अपने गणना प्रपत्र जमा करने में असमर्थ हैं, वे दावा और आपत्ति

अवधि के दौरान निर्धारित घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एसआईआर की गणना के चरण के दौरान, बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्रदान करते हैं। मतदाता विधिवत भरा हुआ प्रपत्र बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अधिकतम क्वरेज सुनिश्चित करने के लिए, बीएलओ प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और सत्यापन के लिए प्रत्येक घर का दौरा करेंगे।

घर-घर जाकर की जाने वाली गणना के दौरान, बीएलओ को कम से कम 30 खाली फॉर्म 6 के साथ-साथ

खाली घोषणा पत्र भी ले जाने होंगे, ताकि वे नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को ये फॉर्म उपलब्ध करा सकें।

राजनीतिक दलों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) को जनता से प्रतिदिन अधिकतम 50 प्रपत्र एकत्र करने और मसौदा प्रकाशन से पहले उन्हें बीएलओ को सौंपने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एसआईआर प्रक्रिया के सुचारु और प्रभावी संचालन में बीएलओ की सहायता के लिए अधिक बीएलए नियुक्त कर सकते हैं।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानूनी मापन सुधारों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

विश्वास-आधारित विनियमन, सरलीकृत अनुपालन और उपभोक्ता संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया।

जीएटीसी नियमों के कार्यान्वयन और पूर्व लाइसेंस-आधारित प्रणाली से पंजीकरण-आधारित प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएटीसी नियमों और पंजीकरण-आधारित ढांचे के कार्यान्वयन के उन्नत चरण में हैं। (जीएनएस)।

देश भर में चल रही क्षेत्रीय समीक्षाओं की श्रृंखला के अंतर्गत, उत्तरी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और लद्दाख में विधिक मापन सुधारों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। यह समीक्षा बैठक जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 और विनियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति (एचएससी) की अनुसंधानों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के

लिए आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव सुश्री निधि खरे ने की।

यह बैठक इसी सप्ताह के प्रारंभ में दक्षिणी राज्यों के साथ आयोजित इसी प्रकार के परामर्शों के बाद हुई और विधिक मापन अधिनियम, 2009 के तहत लागू किए गए हालिया सुधारों के सुचारु, एकसमान और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विभाग के निरंतर सहयोग का हिस्सा है।

बैठक के दौरान, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियंत्रकों और कानूनी मापन अधिकारियों के साथ बातचीत की और अनुपालन बोझ को कम करने, व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए अधिक विश्वास-आधारित नियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से किए गए प्रमुख सुधारों की प्रगति की समीक्षा की।

चर्चा का मुख्य बिंदु वजन और माप के निमाताओं, डीलरों और मरम्मतकताओं के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग प्रणाली को पंजीकरण-आधारित प्रणाली से बदलना था।

राज्यों को बताया गया कि इस सुधार का उद्देश्य केवल "लाइसेंस" शब्द को "पंजीकरण" से बदलना नहीं है, बल्कि नियामक प्रक्रिया को मौलिक रूप से सरल बनाना है। निर्धारित दस्तावेजों को जमा करने पर पंजीकरण स्वतः ही प्रदान किया जाएगा, जिससे देरी कम होगी और व्यवसायों के लिए कानूनी ढांचे के भीतर काम करना आसान हो जाएगा।

विभाग ने जन विश्वास सुधारों के तहत नवगठित "सुधार सूचना" तंत्र के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। इस प्रावधान का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई शुरू होने से पहले पहली बार प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को सूचित करना और प्रोत्साहित

सूचिच्छक अनुपालन को प्रोत्साहित करना है। इस सुधार से अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी आने और अधिक अनुपालन-उन्मुख नियामक

वातावरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

वजन और माप के सत्यापन और मुहर लगाने का मुद्दा भी चर्चा का एक प्रमुख विषय था। राज्यों को सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) ढांचे के विस्तार और स्व-सत्यापन तथा तृतीय-पक्ष सत्यापन तंत्रों की बढ़ती भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे अपने जीएटीसी नियमों को जल्द से जल्द अधिसूचित करें और सत्यापन सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने तथा व्यवसायों के लिए प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए वजन और माप उपकरणों की अधिक श्रेणियों को जीएटीसी ढांचे के अंतर्गत लाएं।

बैठक में डिजिटलीकरण पहलों से संबंधित प्रगति की समीक्षा भी की गई, जिसमें ई-माप पोर्टल, कानूनी मापन अधिकारियों की क्षमता निर्माण और देश भर में सत्यापन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं।

दिल्ली के लाजपत मार्केट में 'कैरीमैन' सेवा: महिलाओं के लिए खरीदारी सहायक, सामान ले जाने से लेकर मार्गदर्शन तक की सुविधाएं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारतीय बाजारों में आपको ज्यादातर महिलाएं ही खरीदारी करती नजर आएंगी। क्योंकि महिलाओं को खरीदारी करना बेहद पसंद होता है, यह एक सर्वविदित तथ्य है। और खासकर महिलाएं तो हमेशा अपने पतियों को अपने साथ रखती हैं ताकि वे उनका सामान उठा सकें। हालांकि, युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक नया उद्यम इस ज़रूरत को भी खत्म करता

नजर आ रहा है। दिल्ली के लाजपत बाजार में युवाओं द्वारा एक अनोखी सेवा शुरू की गई है। ये युवा महिलाओं का सामान हर जगह ले जाते हैं। उनकी टी-शर्ट पर "कैरीमैन" लिखा होता है। वे इस बाजार के मालिक भी हैं, इसलिए वे महिलाओं को उनकी जरूरी खरीदारी में मार्गदर्शन भी करते हैं। इसके लिए वे प्रति घंटे 149 रुपये लेते हैं। यह व्यक्ति आपकी ओर से सामान

उठाएगा, फूड कोर्ट की लाइन में खड़ा होकर नंबर लेगा, बाजार से सामान लेकर आपके साथ मेट्रो स्टेशन तक जाएगा, आपके लिए बैठने की जगह ढूँढेगा और अगर बैठने की जगह नहीं मिली तो फोल्डिंग कुर्सी का भी इंतजाम करेगा।

इस स्टार्टअप की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसमें एक खास स्क्रीम भी शामिल है। जो लोग लंबे समय तक शॉपिंग करना

पसंद करते हैं, उनके लिए दो घंटे, तीन घंटे और चार घंटे की छूट योजना भी है। यह प्रयोग फिलहाल दिल्ली के लाजपत मार्केट में चल रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह अनोखा प्रयोग वाकई स्टार्टअप कहलाएगा या नहीं, या फिर यह एक सफल आइडिया साबित होगा या नहीं? देश के बेरोजगार युवाओं को अब शर्म छोड़कर कुछ शुरू करना चाहिए, यही समय की मांग है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट : भारत में 2024 में दहेज से संबंधित 5,737 हत्याएं हुईं, जिससे पता चलता है कि हर 90 मिनट में एक महिला इस अपराध का शिकार हो रही है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2024 में दहेज से संबंधित 5,737 हत्याएं दर्ज की गईं। इसका मतलब है कि प्रतिदिन लगभग 16 महिलाओं की मृत्यु हुई। यानी दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, आत्महत्या या अन्य संदिग्ध वैवाहिक मौतों के कारण हर 90 मिनट में एक मौत हुई। ये आंकड़े 6 मई को जारी किए गए थे। ये आंकड़े दशकों से लागू कानूनी प्रतिबंधों और

जागरूकता अभियानों के बावजूद दहेज से संबंधित अपराधों की निरंतर व्यापकता को रेखांकित करते हैं। पिछले दशक के आंकड़ों से पता चलता है कि दहेज से संबंधित मौतों में धीरे-धीरे कमी आई है। 2015 में ऐसे 7634 मामले थे, जो 2024 में घटकर 5,737 रह गए। कमी के बावजूद, देश भर में ऐसी घटनाओं की संख्या काफी अधिक बनी हुई है। इस रिपोर्ट में दहेज उत्पीड़न से संबंधित अपराधों में वृद्धि भी दर्ज की गई है।

2013 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत 15,489 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में दर्ज 13,479 मामलों की तुलना में 14% की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, 2024 में देश भर में "पतियों और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" के 12 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो एक दशक से अधिक समय से प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक मामलों के पैटर्न को जारी रखते हैं। आंकड़ों में "दहेज हत्या" के रूप में वर्गीकृत मामले भी दर्ज किए गए हैं,

जो दहेज विवादों से जुड़ी प्रत्यक्ष घातक हिंसा की घटनाओं को संदर्भित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में, एक महिला रहअल कमांडो की उसके पति ने बार-बार दहेज की मांग के कारण हत्या कर दी थी, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक संदर्भ में दहेज से संबंधित हिंसा की निरंतर व्यापकता के बारे में चिंताएं और बढ़ गईं। और फिर भी, यह कहा जाता है कि नारी तू सब पर भारी है।

सीएम का बड़ा एक्शन, कमीशनखोरी करने वाले 2 अधिकारी निलंबित

उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक निदेशक धीरेन्द्र कुमार झा और प्रधान सहायक इमरान अहमद को निलंबित कर दिया है। दोनों पर तबादलों के नाम पर कमीशनखोरी, रिश्तखोरी और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं।

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। विभाग के प्रशिक्षण निदेशालय में तैनात सहायक निदेशक धीरेन्द्र कुमार झा और प्रधान सहायक इमरान अहमद पर गंभीर आरोप लगने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस कदम को राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। ट्रांसफर के नाम पर करते थे धन उगाही

जानकारी के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने दोनों अधिकारियों के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। वहीं निदेशक प्रशिक्षण अभिषेक सिंह ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कराया। विभागीय सूत्रों के मुताबिक सहायक निदेशक धीरेन्द्र कुमार झा पर कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और अपने पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप हैं कि स्थानांतरण स्वर के दौरान विभाग में तबादलों के नाम पर धन उगाही का खेल चल रहा था और इसमें उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई।

बताया जा रहा है कि तबादले करने के लिए संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से मोटी रकम

वसूली जाती थी। सूत्रों का दावा है कि स्थानांतरण करने के बदले करीब 10 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता था। वहीं प्रधान सहायक इमरान अहमद को खिलाफ भी कई गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। उन पर भ्रष्टाचार, कर्मचारियों के उत्पीड़न और धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, विभागीय जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि वह कुछ धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, विभागीय जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि वह कुछ धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, विभागीय जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि वह कुछ धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए गए हैं।

लोगों के साथ मिलकर एक संगठित तरीके से काम कर रहे थे। आरोप है कि अलग-अलग नामों से विभाग में शिकायतें दर्ज कराई जाती थीं और बाद में उन्हीं शिकायतों के निस्तारण का कार्रवाई रोकने के नाम पर संबंधित कर्मचारियों से धन की मांग की जाती थी। इस तरह विभाग में भय और दबाव का माहौल

बनाकर कथित रूप से धन उगाही की जाती थी। सरकारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान सहायक निदेशक धीरेन्द्र कुमार झा को देवीपाराना मंडल से संबद्ध किया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

इस कार्रवाई के बाद व्यावसायिक शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है। विभाग के कर्मचारियों के बीच इस मामले की व्यापक चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने के मूढ़ में नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यूपीएससी छात्रा के साथ तीन दिन तक गैंगरेप, फिर युवती को ट्रेन में बैठाया; इनामी आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप के मामले में नामजद दो आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। (जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप के मामले में नामजद दो आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस की पांच टीमों ने उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थीं, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उधर, पुलिस को आरोपियों के आत्मसमर्पण करने की भी राहें मिलीं। अब पुलिस तैयार कर रही है कि शिनाख्त और गिरफ्तारी में जुटी है।

सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने मुताबिक, गैंगरेप का मुख्य आरोपी शिवम यादव और दूसरा आरोपी शनि है। शनि दिल्लीवर्ती ब्याँय का काम करता है, जबकि शिवम के पिता

प्रयागराज में अधिवक्ता हैं। गैंग रेप के मामले में वांछित एक अन्य आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।



बताया कि गैंगरेप मामले के दोनों आरोपी शिवम और शनि ने शनिवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। उधर, पुलिस को आरोपियों के आत्मसमर्पण करने की भी राहें मिलीं। अब पुलिस तैयार कर रही है कि शिनाख्त और गिरफ्तारी में जुटी है।

जौनपुर से जौनपुर निवासी निजी कॉलेज की बीए ऑनर्स की छात्रा दिल्ली में रहकर वहरउ की तैयारी कर रही है। कॉलेज में छुट्टी होने पर वह एक मई को अपने घर जौनपुर गई थी। यूपीएससी का



एजाम पास आने के कारण वह जौनपुर से 15 मई को दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से निकली थी। पिता ने जाफराबाद रेलवे स्टेशन से सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन से छात्रा को बैठाकर रवाना किया था। छात्रा ने करीबी दोस्त शिवम को किया मैसेज छात्रा के करीब चार साल से परिचित युवक शिवम को उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था। व्हाट्सएप पर बातचीत में शिवम यादव ने छात्रा को चारबाग रेलवे

स्टेशन पर ट्रेन में मिलने आया। आरोप है कि शिवम चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचा और बातचीत के बहाने उसे ट्रेन से उतारकर शहीद पथ क्षेत्र स्थित अपने कमरे पर ले गया।

तीन दिनों तक किया गैंगरेप पीड़िता के अनुसार, वहां उसे कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में अन्य लोगों को बुलाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तीन दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो आरोपियों ने उसे जेनरल टिकट दिलाकर चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठा दिया।

परिजनों को दी पूरी जानकारी ट्रेन में सफर के दौरान छात्रा ने परिजनों को मोबाइल से पूरे मामले की जानकारी दी। परिजनों ने रेलवे पुलिस की मदद ली। इसके बाद दिल्ली के आनंद विहार इलाके में छात्रा के साथ हुई घटना की एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली आनंद विहार पुलिस से जीओ एफआईआर के तहत मामला सुशांत गोल्फ सिटी थाने में स्थानांतरित किया गया था।

लखनऊ से नोएडा की पहली इंडिगो फ्लाइट फुल, रिटर्न जर्नी में मौका

(जीएनएस)। नोएडा: नोएडा एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद उड़ान सेवाएं शुरू होने के मौके पर लखनऊ से नोएडा आने वाली इंडिगो की पहली फ्लाइट के टिकट फुल हो गए हैं। 15 जून की सुबह 07:05 बजे लखनऊ से टिकटऑफ होने वाली फ्लाइट 6ई-2278 की सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। यह फ्लाइट नोएडा एयरपोर्ट पर सुबह

08:05 बजे लैंड करेगी। इस पहली उड़ान में देश-विदेश की नामचीन हस्तियों के साथ राजनीति के धुरंधर भी शामिल होंगे और ऑपरेशन शुरू होने के गवाह बनेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर लखनऊ से आने वाली इस पहली उड़ान को ऐतिहासिक बनाने के लिए इंडिगो अपने नए एयरक्राफ्ट एयरबस अ321 नियो इस्तेमाल करने की योजना बना

रही है। इसमें कुल 195 सीटें हैं, जिनमें 12 बिजनेस क्लास और 183 इकॉनॉमी क्लास की सीटें हैं। यही भी शामिल होंगे और ऑपरेशन शुरू होने के गवाह बनेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर लखनऊ से आने वाली इस पहली उड़ान को ऐतिहासिक बनाने के लिए इंडिगो अपने नए एयरक्राफ्ट एयरबस अ321 नियो इस्तेमाल करने की योजना बना

30 जून तक बदलेगा फ्लाइट टाइम टेबल 15 जून से उड़ान शुरू होने के बाद 30 जून तक फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव किए जा रहे हैं। इसी वजह से फिलहाल टिकट बुकिंग अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, इंडिगो और अकासा एयर एक जुलाई से नियमित रूप से उड़ानों का संचालन करेंगे।

सम्पादकीय

खाड़ी में चल रही जंग के दुष्प्रभावों को समझती जनता चुपचाप सह रही महंगाई

खाड़ी में चल रही जंग से सबक सीखने की आवश्यकता ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग ने जहां पूरे विश्व को प्रभावित किया है वहीं इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक पड़ा है, मजबूर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशवासियों से अपील करनी पड़ी की संकट की घड़ी में पेट्रोल डीजल आदि की खबर को कम करें और देशवासियों ने प्रधानमंत्री की अपील पर सहयोग भी किया है, यहां तक की डीजल पेट्रोल सीएनजी गैस सभी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पर देश में बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त जनता इसको चुपचाप सहन कर रही है और देश में किसी भी कोने में असंतोष पनपने जैसी बातें नहीं उठ रही है चरना इस देश में चुनाव महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़े जाते रहे हैं यहां तक की वर्ष 2009 के चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने 100 दिन के अंदर महंगाई पर रोक लगाने के नारे पर दोबारा जनमत प्राप्त कर लिया था।

यहां तक की 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पाटा के नेताओं ने गैस सिलेंडर की कीमतें 400 रुपये के पास हो जाने के विरोध में मतदाताओं के सामने सिलेंडर लेकर विरोध किया था जहां तक की बात का कार्यकर्ता आटे की कीमत 25 रुपये प्रति किलो होने पर 100 रुपये रिहाडी कमाने वाला मजदूर अपने बच्चों को खिलाएगा वैसे और उनकी शिक्षा और चिकित्सा के बारे में वैसे सोचेगा इन नारों के प्रभाव यह कारण विश्व को आर्थिक मंदी के दौरान देश को सफलतापूर्वक निकलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को वर्ष 2014 के चुनाव में पराजय का मुंह देखा पड़ा था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का करिश्माई ही कहा जाएगा कि आज सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये के पार पहुंच गई है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है और बाजार में सभी आवश्यक खाद्यान्न की कीमत बढ़ाने के पात भी सत्ता धारी भारतीय जनता पाटा विधानसभा के चुनाव लगातार जीत रही है क्योंकि देश की जनता यह जानती है कि खाड़ी में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि के कारण महंगाई पर नियंत्रण मुश्किल हो गया है।

दिल्ली जैसे महानगरों में उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर काम करने वाले मजदूर 5 किग्रा क्षमता वाला मिनी गैस सिलेंडर ना मिल पाने के कारण सब कुछ छोड़-छोड़ कर अपने गांव भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज इन महानगरों में रिहाडी पर काम करने वाले मजदूर मिलने बंद हो गए हैं।

जबकि दो दशक पूर्व तक इनकी रसोई के ईंधन के रूप में मिट्टी का तेल और कोयला प्रयोग होता था, पर अब पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर मिट्टी का तेल और कोयले का उपयोग बंद हो गया है और यह मजदूर पूरी तरह से 5 किग्रा क्षमता वाले मिनी सिलेंडर गैस सिलेंडर पर निर्भर हो गए और जब यह नहीं मिल पा रहा है तो इनका शहर से पलायन करना आवश्यक हो गया है इसके कारण महानगरों में चल रहे विकास और निर्माण कार्य ठप्प पड़ गए हैं।

28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने से पहले कच्चा तेल 60-70 डॉलर. प्रति बैरल था। और अब यह 50डू तक उछाल ले चुका है, सरकारी वंपनियों के लिए विदेशी कच्चे माल का औसत खरीद मूल्य फरवरी में 69 रुपए डॉलर था, मार्च में यह 117.09 डॉलर प्रति बैरल हो गया, अप्रैल में 114.48 प्रति बैरल रहने के बाद मई में अब इसका औसत मूल्य 107.84 प्रति बैरल पर है इसकी की अंतरराष्ट्रीय कीमत 50डू से ज्यादा चली है और एलजीवी का दाम दुगुने से ज्यादा हो चुका है। सरकारी तेल वंपनियों ने 15 मई के बाद चार बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करके इनके दाम 7.5 प्रति लीटर बढ़ाए हैं। दाम न बढ़ने से तेल वंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था और सरकार के कथन अनुसार अगर हालात ऐसे ही रहे तो 3 महीने में सरकारी तेल वंपनियों का मुनाफा समाप्त हो जाएगा, जैसा हम सभी जानते हैं यह तेल वंपनियां अपने लाभ का कुछ हिस्सा सरकार को देती हैं जिस देश के विकास के काम होते।

यूपी में अस्पतालों की हकीकत जानने जमीन पर उतरीं टीमें, सीएम योगी के निर्देश पर 'स्टेट रिव्यू मिशन' से बदला स्वास्थ्य ढांचा

(जीएनएस)। लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार व्यापक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में योगी सरकार द्वारा संचालित "स्टेट रिव्यू मिशन" के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य संस्थानों का बड़े पैमाने पर निरीक्षण और समीक्षा अभियान चलाया जा रहा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, कमियों की पहचान करना और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

29 अक्टूबर 2025 से "स्टेट रिव्यू मिशन" की शुरूआत अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग अमित कुमार घोष ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर नागरिक को उसके घर के पास गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क

स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लगातार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग अमित कुमार घोष द्वारा 29 अक्टूबर 2025 से "स्टेट रिव्यू मिशन" की शुरूआत की गई।

मिशन के तहत प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, गुणवत्ता और प्रभावशीलता की गहन समीक्षा की जा रही है। मंडल स्तर पर संचालित अभियान में स्वास्थ्य इकाइयों का स्थल निरीक्षण, व्यवस्थाओं का मूल्यांकन तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पिछले छह माह के दौरान 18 मंडलों के सभी 75 जिलों और 826 विकास खंडों में

संचालित स्वास्थ्य संस्थानों का बड़े पैमाने पर निरीक्षण किया गया। राज्य स्तर पर विशेष "फैसिलिटी



ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट" विकसित की गई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक एवं स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकी जोवल ने बताया कि अभियान के दौरान प्रदेश की कुल 33,044 चिकित्सा इकाइयों में से 16,249 चिकित्सा इकाइयों का निरीक्षण

किया गया, जो कुल इकाइयों का लगभग 49 प्रतिशत है। निरीक्षण कार्य 901 मंडलीय एवं जनपदीय

अधिकारियों तथा 43 राज्य स्तरीय अधिकारियों की दो सदस्यीय टीमों द्वारा किया गया। इन टीमों ने प्रदेश के 93 जिला अस्पतालों, 861 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 2,825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 12,405 स्वास्थ्य उपकेंद्रों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों,

50 विशेष चिकित्सालयों तथा 15 मेडिकल कॉलेजों का स्थलीय मूल्यांकन किया।

इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित 2,661 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का भी निरीक्षण किया गया। इन स्वास्थ्य मेलों के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुछ मंडलों में निरीक्षण के दूसरे चरण का कार्य भी जारी है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि स्टेट रिव्यू मिशन के तहत निरीक्षण के लिए राज्य स्तर पर विशेष "फैसिलिटी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट" विकसित की गई। इसके माध्यम से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी ढांचे, दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता, मानव

संसाधनों की स्थिति, एंबुलेंस सेवाओं, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपलब्ध सुविधाओं तथा रिकॉर्ड प्रबंधन का मूल्यांकन किया गया। साथ ही रोगियों से फीडबैक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक गुणवत्ता का भी आकलन किया गया।

निगरानी और समीक्षा से स्वास्थ्य संस्थानों की बड़ी कार्यक्षमता स्टेट रिव्यू मिशन के दौरान किए गए गहन निरीक्षण, आकस्मिक जांच और लगातार समीक्षा का सकारात्मक प्रभाव अब प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार दर्ज किया गया है और चिकित्सा संस्थानों में सेवा गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के नए मानक स्थापित हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सतत निगरानी और समीक्षा से न केवल स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ रही है।

शहर-ए-तहजीब में बनेगा ओडीओसी पार्क, लखनऊ में बैठे-बैठे चख सकेंगे पूरे वट का स्वाद



(जीएनएस)।

लखनऊ: राजधानी में बैठे-बैठे ही उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का प्रसिद्ध खाना खा सकेंगे. योगी सरकार की 'एक जिला, एक व्यंजन' योजना को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA गोमती नगर के विभूति खंड में 'ODOC पार्क' विकसित करेगा. यहां दिल्ली हाट की तर्ज पर 40 से अधिक फूड कियोस्क बनेंगे, जहां प्रदेश के अलग-अलग जिलों के परंपरिक और प्रसिद्ध व्यंजन मिलेंगे.

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पिछले

दिनों स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. विभूति खंड में नवनिर्मित गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास करीब 8,000 वर्गमीटर जमीन पर यह पार्क बनेगा. पार्क में

बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी इस योजना के माध्यम से लखनऊ में सभी जिले के लोगों को उनके प्रिय भोजन का स्वाद लेने के लिए अवसर देगी. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के लोग भी उत्तर प्रदेश के मशहूर खाद्य पदार्थों का एक ही जगह पर आनंद ले सकेंगे. एक जिला-एक व्यंजन-जिला-व्यंजन लखनऊ रेवड़ी वाराणसी टमाटर चाट, कचौड़ी-सब्जी, लरसी आगरापेठा, गजक, बेडमी पूरी मेरठ मेरठी बाके, नानखटाई कानपुर लड्डू गोरखपुर खिचड़ी, ठेकुआ प्रयागराज गुजिया, मलाई गिलौरी झांसी पेड़ा, खुरमा अलीगढ़ बेडवी रोटी मथुरा पेड़ा, कचौड़ी मुरादाबाद दालमोट सहारनपुर जलेबी, गुलाब जामुन फैजाबाद मालपुआ आजमगढ़ कलाकंद

बस्ती महेवा का पेड़ा बाराबंकी चिरौंजी का लड्डू सुल्तानपुर मिठाई सीतापुर रेवड़ी, गजक हरदोई टंडई, खुरमा उन्नावसमोसा रायबरेली पुआ, मालपुआ अमेठीरसगुल्ला, छेना जौनपुर इमरती, जलेबी मिजापुर खस्ता कचौड़ी भदोही कचौड़ी-सब्जी चंदौली लिट्टी-चोखा सोनभद्र तिलकुट, खाजा कुशीनगर ठेकुआ, अनरसा देवरिया खुरमा, मालपुआ महाराजगंज मटरी, खस्ता सिद्धार्थनगर तिल का लड्डू बलरामपुर गुलाब जामुन श्रावस्ती शकरपारा बहराइच शीरमाल लखीमपुर गजक, रेवड़ी शाहजंपुर तिलकुट, पेड़ा पीलीभीत रसगुल्ला, बर्फी फरुखाबाद गुलाब जामुन, इमरती

कनौज इत्र वाली मिठाई, पेड़ा इटावा पेड़ा, लड्डू औरियागजक, रेवड़ी बांदा खुरमा, पुआ चित्रकूट मटरी, लड्डू हमीरपुर पेड़ा, जलेबी महोबापान, खुरमा जालौन पेड़ा, गजक ललितपुर मटरी, शकरपारा आशियाना कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक चंद्रमोहन चौबे ने बताया कि लखनऊ में मिलेगा यूपी के हर जिले का स्वाद. योजना का मकसद हर जिले की खास पहचान बने खाने को बढ़ावा देना है. डड्डउ पार्क में आने वाले लोग लखनऊ से बाहर जाए बिना ही अलग-अलग जिलों का जायका ले सकेंगे.

इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

बल्कि छोटे स्तर पर काम करने वाले रसोइयों और फूड विक्रेताओं को भी बड़ा बाजार मिलेगा. डड्डउ पार्क के शुरू होने से लखनऊ फूड लवर्स के लिए बड़ा आकर्षण बन जाएगा. लोग अब हर जिले के खाने का स्वाद एक ही जगह ले सकेंगे.

आरसीबी वर्सेज गुजरात टाइटंस के फाइनल में कौन जीता

(जीएनएस)। अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए गुजरात उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई और 8 विकेट पर 155 का स्कोर ही हासिल कर पाई। आरसीबी ने लक्ष्य हासिल कर लगातार दूसरी बार आईपीएल का टाइटल अपने नाम कर लिया।

गुजरात टाइटंस की शुरूआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन (12) और कप्तान शुभमन गिल (10) पावरप्ले में ही सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद निशांत सिंधु ने 20 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे भी बड़ी पारी नहीं खेल सके।

कहल 2026 डी प्रह्लं' टी डड्डुल्ल खींइ मध्यक्रम में विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने 23 गेंदों में

19 रनों की बेहद धीमी पारी खेली, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया। ऐसे मुश्किल समय में वॉशिंगटन सुंदर संकटमोचक बनकर उभरे। उन्होंने



एक छोर संभाले रखा और 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से नाबाद 50 रनों की जुझारू पारी खेली। सुंदर के इस बेहतरीन अर्धशतक की बदौलत ही गुजरात की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी।

अंतिम ओवरों में अरशद खान ने महज 6 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से

ताबड़तोड़ 15 रन बनाए, जबकि राशिद खान ने भी 3 गेंदों में 7 रन बनाए। आरसीबी के गेंदबाजों ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की, जिसमें रशिख

जड़कर तहलका मचा दिया। आरसीबी का पहला विकेट 62 रन पर गिरा। अख्यर 16 गेंदों में 32 रन बना आउट हुए। उनके बाद देवदत्त पडीक्कल 1 रन बना चलते बने। हालांकि कोहली टिके रहे। उधर रजत पाटीदार 13 गेंदों में 15 रन बना चले गए और स्कोर 89/3 हो गया। उनको राशिद खान ने आउट किया और इसी ओवर में

ऋणाल पांड्या को भी 1 रन पर आउट कर वापस भेज दिया। इन सबके बीच विराट कोहली अपने चेज मास्टर का टैग लेकर आगे बढ़ते चले गए और 25 गेंदों में फिफ्टी जमा डाली, जो आईपीएल में उनका सबसे तेज अर्धशतक है, इससे पहले 26 गेंद में उनकी फारस्टस्ट आईपीएल फिफ्टी थी। उनके साथ खड़े होकर टिम डेविड ने 17 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली। कोहली अंत तक खड़े रहे और टीम को फाइनल में जीत दिलाकर ले गए, उन्होंने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए, उनकी पारी में 9 चौके और 3 चौके आए।

जवाब में खेलते हुए आरसीबी को वेंकटेश अख्यर और विराट कोहली ने मिलकर तूफानी शुरूआत दी। कोहली ने रबाडा के एक ही ओवर में 19 रन

बैटने की जगह, साफ-सफाई और सुंदर लैंडस्केपिंग की पूरी व्यवस्था होगी. शहर-ए-तहजीब में बनेगा 'ODOC पार्क'. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ODOC पार्क से शहरवासियों को एक नया फूड डेरिन्टेशन मिलेगा. साथ ही स्थानीय कारीगरों और फूड उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. पार्क विकसित करने के लिए LDA ने नगर निगम से अनापति प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए हैं.

BJP के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने

'तुमने पुकारा हम चले आए', मशहूर सिंगर सुमन कल्याणपुर का हुआ निधन, कहलाती थीं दूसरी लता मंगेशकर

(जीएनएस)। भारतीय संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। अपनी मधुर और सुरिली आवाज से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाने वाली दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। हिंदी, मराठी, गुजराती समेत कई भारतीय भाषाओं में अपने यादगार गीतों से पहचान बनाने वाली सुमन कल्याणपुर के निधन से संगीत प्रेमियों और फिल्म जगत में शोक की लहर आई। मराठी सिनेमा से शुरू हुआ था

सुनहरा सफर सुमन कल्याणपुर ने अपने गायन करियर को शुरूआत वर्ष 1953 में मराठी सिनेमा से की थी। उनका पहला गीत 'शुक्राची चांदनी' था, जिसने उनके संगीत सफर की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म 'दरवाजा' से बॉलीवुड में कदम रखा और फिल्म के चार गीत गाकर अपनी अलग पहचान बनाई। रेडियो से फिल्मों तक का यादगार सफर बचपन से ही गायन और

चित्रकला में रुचि रखने वाली सुमन ने कॉलेज के दिनों में संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1952 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर गाने का अवसर मिला, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी। इसके बाद उन्हें लगातार फिल्मों में गाने के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महान गायकों के साथ दिए अमर युगल गीत अपने लंबे और सफल करियर के दौरान सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद

रफी, मन्ना डे और तलत महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ कई यादगार युगल गीत गाए। उनकी गायकी की मिठास और भावपूर्ण प्रस्तुति ने उन्हें संगीत जगत की विशिष्ट पहचान दिलाई। 850 से अधिक हिंदी गीतों को दी अपनी आवाज सुमन कल्याणपुर ने हिंदी, मराठी और गुजराती समेत कई भाषाओं में गीत गाए। उन्होंने 850 से अधिक हिंदी गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें 'जिंदगी इन्तेहान लेती है', 'बहाना ने भाई की कलाई में' और आजकल तेरे-मेरे प्यार के चंच जैसे लोकप्रिय गीत शामिल हैं।

कोहली ने जमाया अपने 19 सालों का सबसे तेज अर्धशतक

(जीएनएस)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली, जिसे क्रिकेट फैंस बरसों तक याद रखेंगे। खिताबी मुकाबले के बड़े मंच पर किंग कोहली ने अपने बल्ले से वो गदर मचाया कि विरोधी टीम के गेंदबाज बेवस नजर आए।

इस हाई-वोल्टेज मैच में कोहली ने न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि अपने आईपीएल करियर का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मात्र 25 गेंदों में अपना अर्धशतक (50) पूरा किया। यह उनके आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे तेज अर्धशतक है।

विराट कोहली को ऐसे ही 'चेज मास्टर' या बड़े मैचों का खिलाड़ी नहीं कहा जाता। जब टीम को फाइनल जैसी बड़े मुकाबले में उनसे एक कप्तानी पारी या धमाकेदार शुरूआत की उम्मीद थी, तब कोहली ने 2018 में

राजस्थान और दिल्ली के खिलाफ बनाए अपने 26 गेंदों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नाबाद 75 रन बनाकर वह आरसीबी को लगातार दूसरी बार टाइटल दिलाकर ले गए।

फाइनल में सबसे उम्रदराज प्लेयर आरसीबी के लिए खेलते हुए 37 साल 207 दिन की उम्र में यह अर्वाॉड अपने नाम किया। उनके बाद चेन्नई अपने नाम किया। उनके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फाफ डु प्लेसिस (37 साल 94 दिन, साल 2021) तीसरे और शेन वॉटसन (36

आरसीबी के लिए खेलते हुए 37 साल 207 दिन की उम्र में यह अर्वाॉड अपने नाम किया। उनके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फाफ डु प्लेसिस (37 साल 94 दिन, साल 2021) तीसरे और शेन वॉटसन (36

इंडियंस (MI) ने इस मामले में गजब का दबदबा दिखाया है. उन्होंने कोलकाता के ईंडन गॉटंस में साल 2013 और 2015 का फाइनल जीता, और फिर हैदराबाद के मैदान पर साल 2017 और 2019 में खिताबी जीत हासिल की। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भी चेन्नई के चेंपॉक स्टेडियम को अपना लकी मैदान बनाते हुए साल 2012 और 2024 की ट्रांफियां वहीं चूम्यं। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने भी इस फेहरिस्त में अपनी जगह पक्की करते हुए अहमदाबाद के मैदान पर साल 2025 और 2026 में लगातार दो बार खिताबी जीत का स्वाद चखा है। आईपीएल में एक से अधिक बार 'पर्पल कैप' जीतने वाले गेंदबाज आईपीएल के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज को 'पर्पल कैप' से नवाजा जाता है, लेकिन लीग के इतिहास में सिर्फ चार ही ऐसे दिग्गज गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को एक से ज्यादा बार अपने नाम किया है।



ऑफ द मैच आईपीएल (IPL) इतिहास के फाइनल मुकाबलों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' (POTM) का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की सूची में अनिल कुंबले शीर्ष पर हैं, जिन्होंने साल 2009 में आरसीबी (फ्रंइ) के लिए 38 साल 219 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था। इस खास लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने साल 2026 में

फाइनल का सबसे बड़ा पल? आउट हुए गिल तो मैदान पर दहाड़े कोहली, अनुष्का ने जमकर मनाया जश्न!

(जीएनएस)। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2026 (IPL 2026) के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गेंद के साथ धमाकेदार शुरूआत की। फाइनल मैच में आरसीबी को पहली बड़ी सफलता मिलते ही मैदान से लेकर स्टैंड्स तक का माहौल चर्चा में आ गया है। मैच के तीसरे ही ओवर में गुजरात के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल का विकेट गिरते ही विराट कोहली का आक्रामक जश्न और स्टैंड्स में मौजूद उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का भक्तिमय अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो

रहा है। तीसरे ओवर में हेजलवुड ने दिलाई सफलता टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस को कप्तान शुभमन गिल ने शुरूआती चौके लगाकर सकारात्मक शुरूआत देने की कोशिश की। हालांकि, यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। पारी के तीसरे ओवर में आरसीबी के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे गिल ने हुक करने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई, जिसे आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार

कैच में तब्दील कर दिया। कोहली-अनुष्का ने जीता फैस का दिल शुभमन गिल का विकेट गिरते ही मैदान पर विराट कोहली का उत्साह



चरम पर था। उन्होंने आक्रामक अंदाज में हवा में मुक्के लहराए और दहाड़ते हुए इस बड़ी सफलता का जश्न मनाया। कोहली का यह उग्र रिएक्शन फैंस के बीच काफी पसंद

किया जा रहा है। मैदान पर जहां आक्रामक जश्न चल रहा था। वहीं स्टैंड्स में मैच देख रही अनुष्का शर्मा के रिएक्शन और उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया। अनुष्का ने इस मुकाबले के लिए एक सफेद स्लीवलेस क्रोशिया-स्टाइल निट टॉप और क्लासिक ब्लू डेनिम कैरी की थी। अनुष्का के हाथ में ब्लैक कलर की डिजिटल रिंग फैंस ने ध्यान दिया कि अनुष्का की उंगली में एक ब्लैक कलर की डिजिटल रिंग थी, जो दरअसल एक 'राधा' नाम जाप काउंटर' है। पिछले कुछ वर्षों में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की आध्यात्मिक यात्रा काफी गहरी हुई है, और यह एक्ससेसरी उसी का प्रतीक है।

यूपी बनेगा नशामुक्त: मुख्यमंत्री योगी के विजन से शुरू हुई बड़ी सामाजिक क्रांति, लाखों लोगों तक पहुंचा संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए एक व्यापक जन-आंदोलन चलाया जा रहा है।

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश को नशामुक्त बनाने और भावी पीढ़ी को इस सामाजिक बुराई से सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक व्यापक जन-आंदोलन खड़ा किया गया है। योगी सरकार ने नशे के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए 'जागरूकता' को सबसे बड़ा और प्रभावी हथियार बनाया है। इसी क्रम में मद्यनिषेध विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश भर के युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर नशा विरोधी कार्यक्रम चलाए गए, जिसके सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं।

युवाओं को सही दिशा देने के लिए 1352 प्रतियोगिताएं

योगी सरकार की प्राथमिकता

पीएम स्वनिधि ने किफायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों को सशक्त बनाने के छह साल पूरे किए

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालयश्री मनोहर लाल अग्रतलमा में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों की उपस्थिति में इस अवसर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की औसत आय में 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि भी दर्ज की गई है। पिछले छह वर्षों में देश भर में 75 लाख पचास हजार से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लाभ मिला है: श्री मनोहर लाल (जीएनएस)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख माइक्रो-क्रेडिट योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) ने किफायती, बिना किसी गारंटी के मिलने वाले ऋण, डिजिटल समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों को सशक्त बनाने के छह साल पूरे कर लिए हैं।

इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश, असम,

केवल नशे की रोकथाम तक सीमित नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना है। इसके लिए प्रदेश के स्कूलों और



कॉलेजों में निबंध, भाषण, पोस्टर मेकिंग और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा आयोजित कुल 1,352 प्रतियोगिताओं में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5,404 छात्र-छात्राओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया, ताकि वे समाज में नशामुक्त के

ब्रांड एंबेसडर बन सकें।

राज्य से जनपद स्तर तक 1700 से अधिक संगोष्ठियां मद्यनिषेध विभाग ने इस अभियान

समाज का संकल्प लिया। इसके अलावा, प्रमुख मेलों और त्योहारों पर 356 प्रदर्शनियां लगाकर लोगों को नशे के सामाजिक नुकसान के प्रति सचेत किया गया।

नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मिली नई ताकत आम जनमानस तक सरल, सुबोध और प्रभावी तरीके से बात पहुंचाने के लिए लोक कलाओं का सहारा लिया गया। इसके तहत प्रदेश में 829 सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो और जादुई शो आयोजित किए गए। इन पारंपरिक और मनोरंजक माध्यमों ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि उन्हें नशे की लत से दूर रहने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए गहवाई से प्रेरित किया। तकनीक और लोक कला के इस बेहतरीन समन्वय से योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में विकास के साथ-साथ सामाजिक सुधारों की गति भी उतनी ही तीव्र रहने वाली है।

को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक व्यापक जनसंपर्क किया। वर्ष भर में 40 राज्य स्तरीय और 1,727 जनपद स्तरीय संगोष्ठियों (शैल्लं१२) का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धमाचंचाओं ने हिस्सा लेकर नशामुक्त

था, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक पहचान मिल सके।

इस योजना की उपलब्धियों पर श्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले छह वर्षों में देश भर में 75 लाख पचास हजार से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लाभ मिला है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ 12 लाख से अधिक बिना किसी गारंटी के ऋण मंजूर किए गए हैं। अब तक लाभार्थियों को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

श्री मनोहर लाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में 2 लाख 59 हजार से ज्यादा ऋण दिए गए हैं। इनके जरिए रेहड़ी-पटरी वालों को ₹430 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद दी गई है।

खास तौर पर त्रिपुरा के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 9,300 से ज्यादा ऋण मंजूर किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लगभग ₹15 करोड़ बांटे गए हैं।

श्री मनोहर लाल ने बताया कि पीएम स्वनिधि के जरिए लाखों लोग पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं और औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। इससे वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भरता का रास्ता खुला है।

पिछले छह सालों में इस योजना

का असर हर पहलू से बदलाव लाने वाला रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 34 लाख 81 हजार महिला रेहड़ी-पटरी वालों को सशक्त बनाया गया है। पूरे देश में महिला रेहड़ी-पटरी वालों को 51 लाख 84 हजार ऋण बांटे गए हैं और 55 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की औसत आय में सालाना 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। 30 प्रतिशत से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों ने इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण के अलावा भी क्रेडिट हासिल किया है।

पीएम स्वनिधि की मुख्य उपलब्धियां

1 करोड़ पांच लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए।

योजना के अंतर्गत ₹17,800 करोड़ से अधिक वितरित किए गए।

34 लाख 81 हजार महिला रेहड़ी-पटरी वालों को सशक्त बनाया गया।

स्वनिधि से समृद्धि के अंतर्गत 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार की गई।

केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 1 करोड़ 52 लाख से अधिक कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति में सहायता की गई।

युगी सरकार 2026 की मदरसा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप-10 छात्र-छात्राओं को

यूपी को नशामुक्त बनाने के लिए योगी सरकार का 'महाभियान', चौपालों तक जगाई जा रही जागरूकता की अलख

उत्तर प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया है। इसके तहत प्रदेशभर में प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। (जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे प्रयासों को लगातार गति मिल रही है। योगी सरकार ने नशे के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए जागरूकता को सबसे प्रभावी हथियार बनाते हुए व्यापक अभियान संचालित किया है। मद्यनिषेध विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश भर में युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों के बीच नशा विरोधी कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया गया, जिससे लाखों लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचा।

योगी सरकार की प्राथमिकता केवल नशे की रोकथाम तक सीमित नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराकर उन्हें

स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में भी लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में निबंध, भाषण, पोस्टर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।



1352 प्रतियोगिताओं में शामिल हुए हजारों छात्र-छात्राएं मद्यनिषेध विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कुल 1352 प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया, इनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5404 छात्र-छात्राओं को पुरस्कार और

प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्योंकि युवाओं को सही दिशा में प्रेरित कर नशे के खिलाफ मजबूत सामाजिक वातावरण तैयार किया जा सकता है, इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाए गए, जहां खेलकूद प्रतियोगिताओं और

जनसंपर्क अभियान चलाया। वर्ष भर में 40 राज्य स्तरीय और 1727 जनपद स्तरीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, इनमें शिक्षकों, कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धमाचंचाओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लेकर नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया, इसके साथ ही प्रदेशभर में 356 प्रदर्शनियों की स्थापना कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों और उसके सामाजिक नुकसान के बारे में जानकारी दी गई, मेलों, त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और राष्ट्रीय पर्वों पर विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाया गया।

योगी सरकार में नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जागरूकता को मिली नई ताकत

यूपी के जनसामान्य तक सरल और प्रभावी तरीके से संदेश पहुंचाने के लिए विभाग ने 829 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, जादू, गीत, कव्वाली और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया।

जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया, इन कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर भी सराहना मिली, प्रदेशभर में 1767 संगोष्ठियां, 356 प्रदर्शनियों का आयोजन

योगी सरकार के निर्देश पर मद्यनिषेध विभाग ने राज्य स्तर से लेकर जनपद स्तर तक व्यापक

कंवेन्शन सेंटर में होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का दीक्षा समारोह, परिसर में इस आयोजन पर खर्च होते थे एक करोड़ रुपये

लखनऊ विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह 31 जुलाई को साइंटिफिक कन्वेन्शन सेंटर में आयोजित होगा, जिससे लगभग एक करोड़ रुपये की बचत होगी। बचाए गए धन का उपयोग छ ...और पढ़ें (जीएनएस)।

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह के लिए 31 जुलाई की तिथि प्रस्तावित की गई है। खास बात ये है कि यह समारोह विश्वविद्यालय परिसर के स्थान पर चौक स्थित साइंटिफिक कंवेन्शन सेंटर में होगा, जिसका किराया मात्र एक लाख रुपये है।

अभी तक लवि परिसर में पारंपरिक दीक्षा समारोह के भव्य पंडाल, साज-सज्जा और वाटरप्रूफिंग आदि व्यवस्थाओं में लगभग एक करोड़ की भारी-भरकम धनराशि खर्च

मदरसा बोर्ड टॉपर्स को योगी सरकार का तोहफा, लखनऊ में होगा भव्य सम्मान; टॉप-3 को मिलेंगे टैबलेट

(जीएनएस)। योगी सरकार 2026 की मदरसा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप-10 छात्र-छात्राओं को

हम छात्र कल्याण, डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के विकास और अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं



कहना है कि टेंट और पंडालों पर लाखों-करोड़ों रुपये व्यय करना कतई उचित नहीं है। दीक्षा समारोह से बचाए गए धन का सतुपयोग और नए वित्तीय सुधारों (जैसे कंसर्टेंसी नीति और सेल्फ-फाइनेंसिंग कोर्सेज) से होने वाली अतिरिक्त आय का सीधा उपयोग

के निर्माण में करेंगे। नए कोर्सों से बढ़ेगी आय लवि ने आय बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसके लिए विभिन्न स्वचिंतपोषित एवं आधुनिक पाठ्यक्रमों में 3350 से अधिक नई सीटें बढ़ाई गई हैं। इनमें बीसीए

और पांच छात्राएं शामिल हैं। सभी टॉप-10 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा।

सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के टॉपर्स



छात्र-छात्राओं को सम्मानित करेगी। मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) परीक्षा के टॉप-10 छात्र-छात्राओं को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। इनमें से दोनों वर्गों के टॉप-3 छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए जून के पहले सप्ताह में राजधानी लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार का उद्देश्य मदरसा को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी बनाना है, ताकि अल्पसंख्यक समाज के छात्र-छात्राएं मुख्यधारा से जुड़कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।

80 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं थे पंजीकृत वर्ष 2026 की उत्र. मदरसा बोर्ड परीक्षा में कुल 80,933 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। इनमें से 63,211 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया, इसमें से 55,788 छात्रों ने परीक्षा पास की थी। मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) की मेरिट सूची में टॉप-10 में पांच छात्र

दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिशा आजाद अंसारी ने कहा कि योगी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में गरीब मुस्लिम परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना उनका अधिकार है।

जून के पहले सप्ताह में होगा सम्मान समारोह

राज्यमंत्री दानिशा आजाद अंसारी ने बताया कि जून के पहले सप्ताह में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वर्ग के टॉप-10 छात्र-छात्राओं को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। दोनों वर्गों के टॉप-3 को टैबलेट फोन दिए जाएंगे, जिससे वह अपनी आगे की पढ़ाई और बेहतर ढंग से कर सकें।

सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई थी परीक्षाएं

मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं बीती 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच दो पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली में मुंशी और मौलवी, जबकि दूसरी पाली में आलिम, अरबी एवं परशियन (फारसी) विषयों की परीक्षाएं संपन्न हुई थी।

प्रदेशभर में कुल 277 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा प्रक्रिया को सुनिश्चित और नकलविहीन बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी निगरानी सीधे मदरसा बोर्ड द्वारा की गई थी। परिणामस्वरूप परीक्षाएं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई थी।

उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक के बेलथांगडी में सिरी मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया

'सिरी महिलाओं के नेतृत्व वाले सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास का एक आदर्श है': उपराष्ट्रपति 'विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण सशक्तिकरण पर आधारित होनी चाहिए': उपराष्ट्रपति

'धर्मस्थल सदियों से सद्भाव, सहअस्तित्व और सेवा का जीवंत प्रतीक रहा है': उपराष्ट्रपति

'सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए; जबरन धर्मांतरण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए': उपराष्ट्रपति (जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज धर्मस्थल से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगडी में स्थित सिरी मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया।

सभा को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि समृद्ध ग्रामीण भारत का सपना सही अर्थों में सिरी जैसी संस्थाओं के माध्यम से ही साकार हो सकता है, जिन्होंने आजीविका सृजन और उद्यमिता के जरिए हजारों महिलाओं तथा ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाया है।

श्री क्षेत्र धर्मस्थल द्वारा प्रतिपादित मूल्यों के बारे में बोलते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सभ्यता ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है और इस बात पर जोर दिया है कि भक्ति, धर्म से परे,

सामाजिक सद्भाव और नैतिक शक्ति में योगदान देती है।

धर्मनिरेपक्षता की भावना को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी धर्मों के साथ समान सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए, जबकि किसी भी प्रकार के



जबरन धर्मांतरण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसद एवं सिरी के अध्यक्ष डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े की प्रशंसा करते हुए उनके जीवन को 'समाज के लिए एक संदेश' बताया। उन्होंने कहा कि लगभग छह दशकों से डॉ. हेगड़े ने यह प्रदर्शित किया है कि आध्यात्मिकता किस प्रकार रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन की एक मजबूत शक्ति बन सकती है।

उपराष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण

के क्षेत्र में श्रीमती हेमावती वी. हेगड़े के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक कार्य की सफलता जीवनसाथी के सहयोग और प्रतिबद्धता से ही संभव हो पाती है।

यह कहते हुए कि सिरी आज प्रत्यक्ष रूप से 3,000 से अधिक



व्यक्तियों और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक लोगों, जिनमें से अधिकांश वंचित पृष्ठभूमि की महिलाएं हैं, की आजीविका का समर्थन करता है, उपराष्ट्रपति ने इसे 'अपने सच्चे अर्थों में सामाजिक परिवर्तन' बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकास को मानव जीवन को स्पर्श करना चाहिए और समाज के हर वर्ग में गरिमा, अवसर और आत्मविश्वास का सृजन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए समावेशी विकास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र

मोदी के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण का मूलमंत्र है।

सिरी के विकास की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संस्थान दृढ़ता, नवाचार, त्याग और समर्पण के माध्यम से निर्मित हुआ है। आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को भारत की विकास यात्रा का मार्गदर्शन करना चाहिए। सिरी को राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलणीय मॉडल बताते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान ने यह दर्शाया है कि उद्योग सामाजिक रूप से जिम्मेदार, महिला-केन्द्रित, पर्यावरण के प्रति जागरूक और अत्यंत मानवीय हो सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार के ग्रामीण औद्योगिक इकोसिस्टम पूरे देश में विकसित होंगे।

इससे पहले दिन में, उपराष्ट्रपति ने धर्मस्थल स्थित श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां प्रार्थना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अन्नपूर्णा प्रसाद निलय का भी दौरा किया, भक्तों से बातचीत की और करुणा, समानता एवं भक्ति पर आधारित मंदिर की सामुदायिक सेवा व निःशुल्क सामूहिक भोजन की अटूट परंपरा की सराहना की। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत, राज्यसभा सांसद एवं सिरी के अध्यक्ष डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े, लोकसभा सांसद श्री वृजेश चौटा और सिरी की संस्थापक श्रीमती हेमावती वी. हेगड़े इस अवसर पर उपस्थित थीं।